Validity of Handlooms (Reservation of Articles) for Production Act, 1985

3567. MISS SAROJ KHAPARDE : Will the Minister of TEXTILES be pleased to state :

(a) whether the Supreme Court has recently upheld the constitutional validity of the Handlooms (Reservation of Articles for Production) Act, 1985; and

(b) if so. what action Government have taken or propose to take to implement the provisions of the Act with immediate effect for the benefit of the handloom sector ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY) : (a) Yes, Sir.

Ob) The Government has requested the state Governments to undertake effective enforcement of Handloom Reservation Orders. Similar directions have been, given to the Textile Commissioner.

राजस्थान में कपड़ा मिल

3568. श्री शिव चरण सिंह :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वस्त्र के कुल उत्पादन तथा खपत का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) राजस्थान में कपड़ा मिलों की संख्या कितनी है तथा इनमें से कितनी मिलें अभी भी चल रही हैं और कितनी बंद हो गई हैं;

(ग) कपड़ा मिलों की संख्या के घटने या इन मिलों के बंद होने के क्या कारण हैं;

(घ) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ङ) राजस्थान में उत्पादित कपास की मात्रा कितनी है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) वस्त्र उद्योग से संबंधित सभी क्षेत्रों के वस्त्रों के उत्पादन और खपत के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

(ख) 31-12-92 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में वस्त्र मिलों की कुल संख्या 107 थी । इन मिलों में से 11 एकक बन्द पड़े हुए थे ।

(ग) मिलों के बन्द होने का प्रमुख कारण वित्तीय दिक्कतें थीं ।

(घ) सरकार ने वस्त्र उद्योग के विकास के लिये अनेकों कदम उठाये हैं जैसे कि :--

(1) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना ।

(2) स्थापना/क्षमता के विस्तार से प्रतिबन्ध हटा दिए गए हैं ।

(3) वस्त्र मशीनरी के आयात का उदारीकरण किया गया है और ऐसी मशीनरी के आयात पर सीमाशुल्क कर दिया है ।

(ङ) राजस्थान में वर्ष 1992-93 में 11 लाख कपास की गांठों के उत्पादन का अनुमान लगाया गया है ।

Production and Export of Raw Silk

3569. SHRl KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state :

(a) what is the production of raw silk in the country during the last three years, year-wise;

(b) the exports of raw silk during the above period;

(c) what targets have been fixed for the export of raw silk by the end of Eighth Five Year Plan; and

(d) whether Government have drawn any plan in this matter ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY) : (a) The production of raw silk during the last 3 years was as under :

Year	Production (in tonnes)
1989-90	12016
1990-91	12665
1991-92	11863

(b) to (d) There have been no exports of raw silk in the past three years. However, the export earnings from value added items of silk e.g. textiles, made-ups, readymade garments etc. having been going up steadily.

Closure of Textile Mills and its Processing Units

357C. SHRI MENTAY PADMANABHAM : Will the Minister of TEXTILES be pleased to state :

(a) whether Government are aware that a number of textile mills and its processing units have been closed because of stiff competition from organised mill sector;

(b) whether it is a fact that a number of people employed in these hand processing units have become unemployed: and

(c) if so, what remedial measures are proposed to be taken by Government ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY) : (a) As on 31-1-93, 121 Cotton/Man-made Fibre Textile Mills, affecting 169852 workers are reportedly closed mainly due to strikes, labour troubles, lockouts and financial difficulties. As on 31st March, 1993, 5 (Five) textile processing units are reported to be closed, rendering 270 workers jobless.

(b) Some hand processing units are facing problems due to their inherent nature and small scale operations.

(c) Government have set up a Textile Workers Rehabilitation Fund Scheme to provide interim relief to the woikers rendered jobless due to permanent/partial closure of a mill, which has been registered either with the Textile Commissioner or under the I (D&R) Act 1951.

हैंक यार्न स्कीम

3571. श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हैंक यार्न स्कीम तैयार कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ; और

(ग) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) सरकार ने चालू वर्ष के दौरान अर्थात् वर्ष 1992-93 में कार्यान्वयन हेतु हथकरघा बुनकरों की मिल व गेट मूल्यों पर हैंक की आपूर्ति की एक योजना लागू की है । यह योजना राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है । वर्ष 1992-93 के लिए 10 मिलियन किलोग्राम सूत का लक्ष्य रखा गया है । सरकार राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम को इस योजना के अन्तर्गत कुल सप्लाई किए गए सूत के मूल्य के 2 प्रतिशत की दर से राशि लौटाती है । जो यात्रा व्यय और ऊपरी खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए है ।